	Rate of income-tax
1. Where income does not exceeds Rs. 25,000/-	Nil
2. Where income exceeds Rs. 25,000/-	40% of the amount by which income exceeds Rs. 25,000.".'.

The First Schedule was added to the Bill.

The questions were put and the motions were negatived.

The Second Schedule, the Third Schedule, the Fourth Schedule and the Fifth Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I beg to move.

"That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

I THE BUDGET (UTTAR PRADESH), 1996-97

II THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) NO. 2 Bill, 1996.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the States of Uttar Pradesh for the services of a part of the financial year 1996-97, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

This Bill arises out of a sum of Rs. 15867.28 crores voted by the Lok Sabha on the 12th September, 1996, and Rs. 5081.14 crores charged on the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh as shown in the 'Vote-on-Account' pamphlet circulated along with the Budget papers on the 1st August, 1996. These amounts, inclusive of the amounts authorised for withdrawal under the Uttar Pradesh Appropriation (Vote-on-Account) Act, 1996, have been sought to enable the Government of Uttar Pradesh to meet its essential expenditure during the first nine months of the current financial year (April to December, 1996) pending approval of the whole year's Budget by the appropriate legislature.

The question was proposed.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का बजट इस सदन के सामने रखा है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जिसके लिए सबसे अधिक बार संसद को बजट पास करना पड़ा है क्योंकि वहां की शांतिप्रिय जनता के बीच कुछ ऐसी शक्तियां काम करती रही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शांति को अशांति में बदलने की कोशिश की है।

महोदया, अगर हम पिछले दिनों की घटनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज था और कल्याण सिंह जी चीफ-मिनिस्टर थे। उन्होंने इस देश की जनता को और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को झूठा आश्वासन देकर एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ माहौल तैयार किया जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां एक विवादास्पद धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया। वैसे उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि हम उस

विवादास्पद ढांचे को किसी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे और इस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी मुगालते में रखा और सुप्रीम-कोर्ट में झूठा आश्वासन दिया, झूठा हलफनामा दिया। इससे वहां एक सांप्रदायिक माहौल बन गया था, इसीलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा क्योंकि वहां पर लोग सुरक्षित नहीं थे, गांव-गांव और शहर-शहर के अंदर हाहाकार मच रहा था। ये लोग यही चाहते थे। इन लोगों के हाथ में वहां की सत्ता आ गई थी और ये वहां शांति नहीं चाहते थे। ये केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे और लोगों को शांति से जीने नहीं देना चाहते थे।

महोदया, बाद में माहौल ठीक होने पर वहां चुनाव हुआ। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त दी और उनको हराया। जनता ने उनको दोबारा राज में नहीं आने दिया और वहां पर एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति चीफ-मिनिस्टर बनाया गया। दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और जनता ने उनको अपना बहुमत दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि वहां पर दलित और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने यह बात फैला दी कि इस सरकार से दलितों का कोई हित नहीं हो रहा है बल्कि अहित हो रहा है। इस तरह उन्होंने उनमें फूट पड़वा दी और बाद में एक दलित महिला को चीफ-मिनिस्टर बनवा दिया। इससे लोगों में यह भावना जागी कि जब इन्होंने एक गरीब और दलित शैड्यूल्ड-कॉस्ट की महिला को चीफ-मिनिस्टर बनवाया है तो इनमें गरीबों और दलितों और शैड्यूल्ड-कास्ट के लोगों के प्रति अच्छी भावना है। लेकिन इनके मन में जो पाप था वह 4 महीने में सामने आ गया। इनके मन में यह पाप था कि अगर दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों को लड़वा दिया जाए तो हम वापस राज में आ सकते हैं। इनके मन में यह मंसूबा था, इसलिए मायावती को चीफ-मिनिस्टर बनवाया गया। लेकिन आपके पाप का घड़ा जल्दी ही फूट गया और आपने 4 महीनों में ही उनमें फूट डलवाकर उनको हटवा दिया। इस बात से यह पता चल जाता है कि आप लोग कितना शैड्यूल्ड-कॉस्ट और शैड्यूल्ड-ट्राईब्ज के लोगों का हित चाहने वाले हो। आपके दिल के अंदर शैड्यूल्ड-कॉस्ट और शैड्यूल्ड-ट्राईब्ज के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वजह केवल यह है कि आपकी स्वार्थ सिद्धि होती रहे, शैड्यूल्ड कॉस्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग मूर्ख बनते रहें और आपकी सपोर्ट करते रहें। महोदया, इस कारण यू॰पी॰ के अन्दर राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करनी पड़ी। आज यू॰पी॰ के बजट की बात करें, तो इस बजट के अंदर केवल अधिकारियों ने आंकड़े जुटा दिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रांत है। ...**(समय की घंटी)**... यदि उसके बजट की बात करें, तो यह जो यू॰पी॰ में चुनाव अक्तूबर के महीने में होने जा रहे हैं यदि यह दो महीने पहले होते तो आज यू॰पी॰ की विधान सभा इस बजट को पास करती तो वहां की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनका निवारण होता, कई समस्याएं दूर होती। वहां राष्ट्रपति शासन है और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में सत्ता की डोर है तथा उन्होंने जो भी आंकड़े बना दिए। उससे पहले भी बजट पेश किया। लेकिन जो काम होना चाहिए, बजट का वहां सदुपयोग नहीं हो पाया। न कहीं सड़कों का काम हुआ। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में सड़कें भयंकर रूप से खराब हैं। वहां की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का वातावरण दूषित हो चुका है। वहां केवल दो तरह की शिक्षा देने वाले लोग, कुछ धर्मों के लोग, अपनी-अपनी विचार-धारा का प्रचार करने वाले लोग अपने स्कूल चलाते हैं। वास्तविक शिक्षा ही वहां मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही है। बल्कि शैड्यूल्ड कॉस्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स की महिलाओं की तो दुर्गति है उस प्रांत के अंदर। वह वहां सुरक्षित नहीं हैं। उन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ अत्याचार होता है, लोगों की जमीनें छीनी जाती है, वहां की बहन-बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और यह केवल शैड्यूल्ड कॉस्ट के लोगो के साथ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उस प्रांत के अंदर शैड्यूल्ड कॉस्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग कुछ जागृत हुए हैं। ...**(समय की घंटी)**... वे पौलिटिकल दृष्टि से जागृत हुए है। तो मैं यह चाहूंगा कि शैड्यूल्ड कॉस्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स की महिलाओं के साथ राष्ट्रपति शासन के दौरान जो बलात्कार हुए हैं, उन महिलाओं की रक्षा के लिए तथा जिन शैड्यूल्ड कॉस्ट के लोगों की हत्याएं करदी गई हैं उनके परिवार के पालन-पोषण के लिए माननीय मंत्री जी अपने इस बजट के अंदर उनको अनुदान देने के लिए, उनके परिवार के पालन-पोषण के लिए कुछ व्यवस्था करें तो इससे शैड्यूल्ड कॉस्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों को लाभ मिलेगा, उनका परिवार चल सकेगा। पिछले दिनों यह देखने में आया कि ...**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude.

श्री मूलचन्द मीणा: मैड्म, मैं कांक्लूड कर रहा हूं। अखबारों में देखने को मिला कि कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, कहीं शैड्यूल्ड कॉस्ट के लोगों की जमीन छीन ली गई, कहीं उनकी बहन-बेटियों की इज्जत लूट ली गई, कहीं किसी को मार दिया गया। ऐसी घटनाएं यू॰पी॰ के अंदर हुई हैं। तो जो लोग पाप का घड़ा हृदय के अंदर लेकर बैठे तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक दलित महिला को फिर दोबारा मुख्य मंत्री बनाएं तो साबित होगा कि आपके दिल के अंदर शैड्यूल्ड कॉस्ट के प्रति कितना भावना है, यही बात मैं कहना चाहता हूं और जो बजट है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Before I call Smt. Malti Sharma, I would like to say that the BJP has 11 minutes and there are four speakers. So, if I ring the bell, please don't complain.

श्रीमती मालती शर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलती हूं। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे इतनी जरूरी अपेक्षा करती हूं कि जो मेरे भाई ने बोला है उसकी सच्चाई आपके सामने अवश्य रखूंगी।

महोदया, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहती हूं कि पूरी जिंदगी गुजर गई घाटे का बजट सुनते-सुनते। मैं यह समझती हूं कि बजट बनाने वाले हमारे मंत्री महोदय यहां उपस्थित है, और जिंदगी में केवल एक साल ऐसा आया था जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और वह बनी थी सन् 1967 में जिसके मुख्य मंत्री थे—चौधरी चरण सिंह और उप मुख्य मंत्री थे राम प्रकाश गुप्त जी। वह वर्ष मेरी जानकारी में है कि कई टैक्सेज माफ किए गए थे और सरकार ने सर्प्लस का बजट पेश किया था। मेरी समझ में नहीं आता, एक साधारण सा उदाहरण मैं देना चाहती हूं कि अगर एक दर्जी कुर्ता सीने के लिए कपड़ा तय करता है कि वह तीन मीटर में बनेगा, तो वह भी दो इंच बचा लेता है। यह कैसे बजट पेश होता है और किस तरह से बजट बनता है कि हमेशा घाटे के बजट पेश होते हैं और जहां घाटे का नाम आता है तो जनता के हृदय में एक भय उत्पन्न होता है कि अब न जाने कितने टैक्सेज बढ़ेंगे।

इसमें मेरा निवेदन है कि इसका स्वरूप बदला जाना चाहिए और इसमें ऐसे शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे जनता के हृदय से भय मिटे। मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं कि बजट पेश करते समय हम जो भी योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं के लिए जो पैसा देते हैं, उसका कुछ समय निर्धारित होना चाहिए कि कितने समय के अंदर वह काम पूर्ण कर लिया जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि मोदीनगर से मेरठ तक के लिए रेलवे की डबल लाइन बिछाने की दो वर्ष पहले घोषणा कर दी गई थी लेकिन आज तक जमीन पर कहीं वह रेल लाइन बिछाने का काम नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं, सवेरे भी रेल मंत्री महोदय कई घोषणाएं कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बजट बनाते कुछ और हैं, घोषणाएं होती कुछ और हैं लेकिन उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए कागज पर हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के बारे में जहां तक मेरे भाई ने कहा है, मैं उसका जवाब भी दूंगी लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक आवाज लगाई—"लाल किले से आई आवाज, उत्तराखंड राज्य हम ला रहे हैं आज।" मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे उत्तराखंड राज्य आ जाएगा। उत्तराखंड के जिन लोगों ने रामपुर के तिराहे पर अपने खून की होली खेली, जिनकी मां-बहनों की इज्जत लूटी गई, तब किसका शासन था? मैं अपने भाइयों से पूछना चाहती हूं कि अगर आप ईमानदारी से सदन को बताना चाहते हैं तो कल्याण सिंह के शासन काल के और मुलायम सिंह के शासन काल के, जिन्हें आपने पुरस्कार दिया है, रक्षा मंत्री बना दिया है, आंकड़े लाकर यहां प्रस्तुत करें कि महिलाओं की इज्जत किसके शासन काल में लुटी? दंगे किसके शासन काल में ज्यादा हुए? ये सारे कांड किसने कराए हैं? उत्तराखंड का यह हाल किसने बनाया है? उत्तराखंड के राज्य के बारे में तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि जिन-जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिन महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उन महिलाओं को बीस-बीस लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दिया जाए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या उनको मुआवज़ा दे दिया गया या उन्होंने इस बजट में उसके लिए कोई प्रोविज़न किया है? मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि उत्तराखंड राज्य की घोषणा क्या आप ईमानदारी से कर रहे हैं? घोषणाएं तो प्रधान मंत्री जी बहुत कर रहे हैं। अगर घोषणाओं से ही काम चलता है तो प्रधान मंत्री जी को दौरे करने की क्या आवश्यकता है? वे क्यों सिसौली भाग गए? क्यों आजमगढ़ भाग गए? घोषणा कर दी होती लाल किले से। किसानों को जो देना चाहते

थे, उसकी घोषणा कर दी होती। उत्तराखंड राज्य देने की खाली घोषणा है। अगर यह उत्तराखंड का राज्य देना था तो पहले उसके लिए कोई मसौदा तैयार किया जाता, कोई बिल लाया जाता, इस तरह से घोषणाएं करने से क्या लाभ होने वाला है?

महोदया, किसानों के बारे में ये बड़ी-बड़ी घोषणाएं करके आए हैं। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि जितनी घोषणाएं करके आए हैं, किसानों का जो बकाया है, उस बकाए का ही भुगतान आप करा दीजिए, उसके लिए तो कोर्ट आदेश कर चुका है। उसके विषय में आप क्या कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के बजट में किसानों का जो बकाया है, मंत्री महोदय उसका भुगतान कराएंगे?

महोदया, इससे आगे भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। किसानों की जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश में है, उससे किसान समझ चुका है कि इन घोषणाओं के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। आप जाकर यह देखिए कि किस तरह से किसानों ने गन्ना खेत में जलाया है। जिन-जिन क्षेत्रों में गन्ने की पिराई के लिए मिलें नहीं है, क्या मंत्री जी वहां नई मिलें देने की घोषणा करेंगे? मैं आपकी जानकारी में ला देना चाहती हूं कि रोहाना शुगर मिल खड़ी है, ढांचा खड़ा है लेकिन मशीनरी नहीं है। छह साल बीत चुके हैं, किसान प्रदर्शन करते-करते, धरने देते-देते थक चुके हैं लेकिन आज तक पैसा नहीं दिया गया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि उस मिल को तुरंत चालू कराइए, उस क्षेत्र में किसानों की बहुत दुर्दशा है।

महोदया, एक बात मैं और कह देना चाहती हूं। पुलिस पर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी, जिस मायावती को हमने मुख्य मंत्री बनाया, उसी मायावती का उन्होंने क्या हाल किया? उस गेस्ट-हाऊस में उसकी क्या दुर्दशा कराई? मैं पूछना चाहती हूं, आप जवाब दीजिए। यह वोट आन अकाउंट नहीं है। अगर आपने कहा है कि हमने वहां झगड़े कराए, हमने फसाद कराए तो हम भी आपसे जवाब मांगना चाहते हैं। अब तो रमेश कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। जो संबंधित व्यक्ति है, जिसने वहां यह सब कुछ कराया है, उसको आप क्या सजा देना चाहते हैं? उसको तो आपने पुरस्कार दिया है, रक्षा मंत्री बना दिया है जो सीमाओं की रक्षा करेगा। एक छोटे से प्रांत में जो आंतरिक व्यवस्था काबू में नहीं रख सका, वह सीमाओं की रक्षा करेगा? आपने तो उसे पुरस्कार दिया है। महोदया, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे आपकी घंटी का डर लगा रहता है।

मेरे ऊपर घंटी बहुत बजती है, मैं इस घंटी से बचना चाहती हूं। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूं कि जब से वहां पर गवर्नर रूल हुआ है तब से वहां का ढांचा बिल्कुल चरमरा गया है। वहां आए दिन चोरी डकैती, लूट-पाट, महिलाओं की इज्जत लूटना, गोली चलना आम बात है। मेरे जिले में 15-15 लाशें एक दिन में पोस्ट-मार्टम के लिए आती हैं। एक बात और कहना चाहूंगी कि थोक में जो ट्रांसफर किये जाते हैं, गवर्नर के शासनकाल में, यह सब कुर्सी बचाने के लिए नहीं है तो किस लिए? चुनाव में मोहरे फिट किये जाते हैं। एक बात और कहना चाहती हूं। पिछली सरकार ने एक करोड़ रुपये की योनजा बनाई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं लेकिन उस एक करोड़ की योजना में भी मैं आपके सामने निवेदन कर रही हूं कि संपूर्ण सदन के भाई बता दें कि एक करोड़ की योजना का उस जमीन पर क्या कहीं उपयोग हो रहा है? मैं आपको बताना चाहती हूं कि वहां पर यह स्थिति है कि आपके अधिकारी, जिन अधिकारियों को आपने उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली है, वह अधिकारी कहते हैं कि 22 परसेंट पहले निकालकर हमें दे दो, उसके बाद आप जहां सड़कें बनाएंगे, जहां आप जो कुछ बनाएंगे, हम खर्च कर देंगे।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) पीठासीन हुई]

मैं एक बात सरकार से पूछना चाहती हूं कि इस बर्तन में, जिसमें आप जनता की गाढ़े पसीने की कमाई डालते चले जा रहे हैं, उस बर्तन का सुराख आप बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? सुराख बंद करने को तो आप तैयार नहीं हैं, उसके बदले घाटे के बजट को आप हमेशा पेश करते रहेंगे, लोगों पर टैक्स थोपते रहेंगे और लोगों को इस तरह से लूटकर गरीबों को और गरीबी तक ले जाने के लिए आप मजबूर करेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि मेरे सारे बंधूओं को इस बात की कसमसाहट होगी। इस एक करोड़ की योजना के लिए कोई कमेटी बननी चाहिए और उस कमेटी का चेयरमैन यहां का सदस्य होना चाहिए। उस कमेटी के अंडर में यह सब काम होना चाहिए। क्या मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे? बोलने को बहुत कुछ है। कमला सिन्हा जी चेयर पर बैठी है। मैं निवेदन करती हूं कि अगर आप कुछ और इजाजत दें तो मैं बताऊं, अन्यथा अगर आपकी घंटी बजने वाली हो तो मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि उत्तराखंड राज्य अगर देना है तो उसके लिए इमानदारी से योजना बनाइए। किसानों को कुछ देना है तो उसके लिए ईमानदारी से योजना बनाइए।

जगह-जगह पर मिलें खोलिए, उनके गन्ने की सुरक्षा कीजिए, उनकी खेती की सुरक्षा कीजिए, उन्हें जो कुछ प्लानिंग चाहिए, वह उन्हें दीजिए। महोदया, महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने तो यहां सदन में कहना ही बंद कर दिया है। अखबार का शायद कोई भी ऐसा शुभ दिन नहीं होता जिस दिन महिलाओं पर होने वाले जुर्म की कहानी न छपी हो। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप बजट बनाते हैं तो पुलिस पर, फौज पर और अन्य विभागों पर तो ध्यान देते हैं लेकिन शिक्षा, जो सबसे पहला विभाग है, जो बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप आंकड़े तो दे देते हैं किन्तु उन आंकड़ों का कहां तक प्रभावी असर होता है, यह समझ में नहीं आता है। हालत यह है कि जो डेवलप्ड इलाके हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें भी ऐसे-ऐसे स्थान हैं जहां 14-14 किलोमीटर तक आज भी कोई विद्यालय नहीं है। आपकी योजना कहां बन रही है? मैंने देखा है, हम एच०आर०डी० की मीटिंग में गये हैं, वहां पर हम देखते है कि बड़े-बड़े अधिकारी लोग आते हैं, उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती, हम गंवार लोग हैं। वह विदेश से पढ़कर आते हैं और विदेशी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमें केवल स्लाइड्स दिखाई जाती है कि हमने यह योजनाएं बनाई है। हम यह मांग करते हैं कि कृपया हमें दिखाइए कि ये योजनाएं कहां-कहां चल रही हैं। हम धक्के खाएंगे, जमीन पर घूमेंगे और आपको सब रिपोर्ट लाकर देंगे कि यहां बालवाड़ी योजना चल रही है, यहां शिक्षा की योजना चल रही है। आप प्रौढ़ शिक्षा की योजना बनाते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि बूढ़ों को तो आप बाद में पढ़ाइएगा, पहले बच्चों को तो पढ़ा लो। बच्चों के लिए तो विद्यालय नहीं खोले जाते हैं और बूढ़ों के लिए योजना बना रहे हैं। इस तरह से जनता की गाढ़े पसीने की कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि इसको आप कट करिए और किसी निर्माण कार्य में इस धन को लगाइए। आप अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारिए, खाली हवा में चलाने से काम चलने वाला नहीं है। इसी के साथ उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरी बात को धैर्य से सुना।

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Madam Vice-Chairman, we generally exstend our support to the Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill. But we would like the Finance Minister to look into certain areas which we feel have been under-emphasised in the proposition. Uttar Pradesh, as all of us know, is a classic example of synthesis of both Hindu and Islamic culture. It has within its possession the culture of Buddhist and Jain religion as well. From Ramanand to Birbal, Kabir to Tulsidas, many other eminent litteratures of different religio-ethnic origins have been born in Uttar Pradesh.

This pride of us should be properly maintained and promoted particularly in view of the fact that this larger State of this country has witnessed many communal conflagrations in the recent past. If the Government had paid better attention to the promotion of cultural synthesis which this largest State of our country possesses, it would have been better for promotion of communal harmony and for promotion of the entire State.

Madam, in Uttar Pradesh we have seen many constituencies have been developed over the years. But, but being the largest Assembly and the largest State of our country, the infrastructure of the State as a whole remains one of the weakest in India. It needs to be attended to with all gravity because it is the largest producer of sugarcane, foodgrains and many other items including *vanaspati*, cotton yarn, etc. Unless the irrigation potentials are properly attended to and proper infrastructure is created throughout the State, apart from developing the constituencies, we cannot do justice to the even development of the State and thereby of the country as a whole. Sir, here particularly the question of power sector is very impotant. We have an uneven ratio of hydel and thermal power generation in our country. The ideal ratio for a country is 40 and 60 per cent. In our case, it is 24 to 76. We have a great potential. Uttar Pradesh is geologically sub-divided into three parts. But, the Himalayan part to which I am referring, has a great potential of hydro electric power generation. Power generation, particularly hydro-electric, requires a long gestation period. It is the dual responsibility of the Central Government and the State Government according to

our Constitution. So, the Central Government as well must pay adequate attention to the possibilities and potentialities of hydro electric generation in the Himalayan terrain region of Uttar Pradesh.

Madam, I must refer to one another important aspect and this is with regard to the campus situation in Uttar Pradesh. There is a critical phase going on in the campuses of higher education throughout the country. But, the case of Uttar Pradesh is the worst. The Allahabad University held it Law examinations last time in 1992. Similarly, the Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University is calling external police forces and paramilitary forces into the campus on so many occasions. It has happened frequently for the last three years when that police forces entered into the University. This reflect its condition. The vacancies of Vice-Chancellor to other teaching and non-teaching staff are remaining unfilled for years together as a result of which examinations are not being held in time. Syllabi are not being completed properly. More than 30 per cent of the vacancies are remaining unfilled for which the Government should have paid proper attention. There are Central Universities also there which are suffering a tremendous chaos and there is anarchy within the campuses. In certain cases, and particularly in the Banaras Hindu University, the Vice-Chancellor has been accused of organising meetings of a particular political party four times in a year by mising the campus halls, his authority and the entire premises of the University. This cannot go on; this cannot happen. If this goes on like this, there will not be promotion of a healthy atmosphere in the society of Uttar Pradesh as a whole. Unless we promote a healthy atomsphere there will be many other social tensions, apart from communal tension. In this regard, I want to point out that there is an urgent requirement of modernisation of police forces in Uttar Pradesh. When I talk of modernisation of police forces, it is not in terms of providing them modern and scientific weaponary. Here I am talking of modernisation of the conception of the police forces—the scientific and modern orientation of the police forces. They should not be misled; they should not be partisan while tackling communal conflagrations.

They should not be partisan while tackling any kind of social or political tension. For this, training, modern scientific training, to the entire force is necessary, which is overdue in the case of B.S.F. and other para-military forces of Uttar Pradesh. With these words I conclude. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): It is good that you have finished, otherwise, I was going to tell you that your time was over. Dr. Ranbir Singh—absent. Shri Jalaludin Ansari.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): श्री जलालुदीन अंसारी जी, आपके पास एक मिनट 30 सैकेन्ड्स का समय है, एकदम गागर में सागर भर दीजिये।

श्री जलालुदीन अंसार (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में अभी राष्ट्रपति-शासन लागू है इसलिए संसद में उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के बजट का समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बजट में, उत्तराखंड के पिछड़े इलाके के विकास के लिए क्या विशेष धन की व्यवस्था की गई है? इसके साथ ही यह भी बताया जाये के क्या इस बजट में दलितों, पिछड़े लोगों के लिए कोई विशेष धन की व्यवस्था की गई है तथा गन्ना उत्पादक किसानों के लिए उनकी बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है या नहीं? यह प्रदेश कुछ दिनों से राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पूरा देश जानता है कि इस प्रदेश में किस तरह से साम्प्रदायिक जातीय भावनाओं को उत्पन्न किया गया। इस राज्य में तरह-तरह की साम्प्रदायिक और जातीय दुर्घटनाएं हुई और जो भी सरकार बनी वह इन कारणों से जाती रही। खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। राज्य के मतदाता अपने अनुभव की बुनियाद पर यह तय करेंगे कि इस प्रदेश में प्रशासन चलाने के लिए, राज चलाने के लिए कैसे प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाये?

मैं आशा करता हूं कि इस चुनाव में इस प्रदेश के मतदाता, साम्प्रदायिक ताकतों को परास्त करेंगे और लोकतांत्रित, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की सरकार बनायेंगे। यदि आज वहां सरकार होती तो राज्य की आवश्यकता के अनुरूप बजट बनाती और राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए वह काम करती। लेकिन अभी राष्ट्रपति शासन के दौरान जो वहां से सुझाव आये हैं, उनके आधार पर यह बजट, 1996-97 का पारित किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि जो नई सरकार बनेगी वह अपने राज्य के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने बजट का निर्धारण करेगी और जो चुनाव के नतीजे आयेंगे उन्हीं के आधार पर राज्य के विकास की बात भी निर्धारित की जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के बजट का समर्थन करता हूं।

†[شری جلال الدین انصاری (بہار):
آپ سبھا ادھیکش مہودے - اترپردیش میں ابھی راشٹرپتی شاسن لاگو ہے اسلئے سنسد میں اترپردیش کا بجٹ پیش ہوا ہے - میں اترپردیش کے بجٹ کا سمرتھن کرتا ہوں - اترپردیش دیش کا ایک بڑا راجیہ ہے - میں مانیہ منتری جی سے یہ جاننا چاہونگا کہ اترپردیش کے بجٹ میں اتراکھنڈ کے پچھڑے علاقوں کے وکاس کیلئے کیا "وشیش" دھن کی "ویوستھا" کی گئی ہے - اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا جائے کہ کیا اس بجٹ میں دلتوں پچھڑے لوگوں کیلئے کوئی وشیش دھن کی ویوستھا کی گئی ہے - تتھا "گنا" اتپادک کسانوں کیلئے ان کی بقایا راشی کے بھگتان کی ویوستھا کی گئی ہے یا نہیں - یہ پردیش کچھ دنوں سے راجنیتک "استھرتا" کے دور سے گزر رہا ہے - پورا دیش جانتا ہے کہ اس پردیش میں طرح طرح کی سامپردائک اور جاتیہ درگھٹنائیں ہوئیں - اور جو بھی سرکار بنی وہ ان کارنوں سے جاتی رہی خوشی کی بات ہے کہ اترپردیش میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں - راجیہ کے "متداتا" اپنے انوبھو کی بنیاد پر یہ طے کریں گے کہ اس پردیش میں پرشاسن چلانے کیلئے - راج چلانے کیلئے کیسے پرتی ندھیوں کا چناؤ کیا جائے - میں آشا کرتا ہوں کہ اس چناؤ میں اس پردیش کے متداتا سامپردائک طاقتوں کو پراست کریں گے اور لوکتانترک - دھرم نرپیکش شکتیوں کی سرکار بنائیں گے - اگر آج وہاں سرکار ہوتی تو راجیہ کی آوشیکتا کے انوروپ بجٹ بناتی اور راجیہ کے "چہو مکھی" وکاس کیلئے وہ کام کرتی - لیکن ابھی راشٹرپتی شاسن کے دوران جو وہاں سے سجھاؤ آئے ہیں - انکے آدھار پر یہ بجٹ 97-1996 کا پارت کیا جا رہا ہے - ہم آشا کرتے ہیں کہ جو نئی سرکار بنیگی وہ اپنے راجیہ کے وکاس کی آوشیکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے بجٹ کا نردھارن کریگی اور جو چناؤ کے نتیجے آئیں گے انھیں کے آدھار پر راجیہ کے وکاس کی بات بھی نردھارت کی جائیگی -]

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

انھیں شبدوں کے ساتھ میں اتر پردیش کے بجٹ کا سمرتھن کرتا ہوں۔ "ختم شد"]

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): रामनाथ कोविन्द जी, आप यदि नहीं बोलना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है और यदि बोलना चाहते हैं तो आपके पास दो-तीन मिनट का समय है, बोलिये।

श्री रामनाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश) मैडम, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश के बजट पर बोलने का मौका दिया। जब मुझे यह जानकारी मिली कि यह बजट सरप्लस बजट है, पांच करोड़ का, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन जब देखा कि यह सरप्लस बजट कैसे हो गया तो मुझे दुख भी बहुत हुआ और ऐसा लगा कि यह बजट तो it is a misleading and deceptive Budget.

यह इस सेंस में सब को भ्रामक करने वाला है कि जवाहर रोजगार योजना की जो ग्रांट होती थी वह अभी तक डाइरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जाती थी। अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि वह डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में यह हमारा सरप्लस बजट हो गया।

महोदया, वहां पर जैसा कि सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन चल रहा है और वह 17 अक्तूबर को समाप्त होने वाला है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो राज है वह करीब-करीब एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत, जो कि वहां से राज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है, उसके तहत उसकी अवधि पूरी होने वाली है। महोदया, इस बीच में वहां दो राज्यपाल आए। पहले वाले राज्यपाल, महामहिम मोतीलाल वोरा थे और जब वे चले गए तो महामहिम श्री रोमेश भंडारी वहां के राज्यपाल हैं। दोनों ही राज्यपालों के शासन में जो राजभवन था, महोदया, राजभवन मुख्यरूप से प्रदेश के सारी जनता के लिए होता है वह प्रदेश के सभी राजनैतिक दलों के लिए समान होना चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि जो केन्द्र में रूलिंग पार्टी वह उसका हैडक्वार्टर बनकर रह गया है। यही बात पिछले राज्यपाल के दौरान हुई और यही बात इस राज्यपाल जी के शासन के दौरान है। महोदया, यह हम सब को आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने तो यहां तक किया कि राजभवन में आफिशियल मीटिंग बुलाई, जिसका वहां पर प्रतिरोध हुआ। दूसरे दिन पत्रकारों ने और उत्तर प्रदेश के सभी अखबारों में इस बात का विरोध किया गया केन्द्र का मंत्री...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अब आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Who held a meeting? You say that the Finance Minister held a meeting in the Raj Bhavan.

SHRI RAM NATH KOVIND: He held a meeting.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Whom are you referring to?

SHRI RAM NATH KOVIND: Mr. Mulayam Singh Yadav. He held an official meeting.

SHRI P. CHIDAMBARAM: You mean the Defence Minister?

SHRI RAM NATH KOVIND: Defence Minister; in the Raj Bhavan.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अब आप समाप्त करें।

श्री रामनाथ कोविन्द: हमारे चार सदस्य बोलने वाले थे, उनमें से केवल तीन रह गए हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): चार सदस्य थे लेकिन आपका टोटल 11 मिनट का समय था। आपका 11 मिनट का समय समाप्त हो चुका है।

श्री रामनाथ कोविन्द: मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल का शासन है उस शासन में वहां की आम जनता त्रस्त रही है। हमेशा हम सब लोग कहते हैं कि जो रिप्रेजेन्टेटिव गवर्नमेंट होती है, वह हमेशा ठीक रहती है। लेकिन उसकी अवधि 6 महीने थी, उसको जानबूझकर, राजनैतिक कारणों से बढ़ाया गया। एक साल होने वाला है लेकिन वहां की जनता ने इसको कभी पसंद नहीं किया है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि वहां के जो राज्यपाल हैं उन्होंने राजनैतिक नजरिए से काम किया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी अभी जब वहां गए तो उन्होंने कानपुर में जनसभा की और उसकी आफिशियल मीटिंग बताया। उसमें राजनैतिक भाषण दिया गया और खुलेआम फूलबाग में मीटिंग की गई। बहुत बड़ी जनसभा थी और सारा खर्चा सरकार की ओर से दिया गया। प्रधानमंत्री जी अभी जब वहां गए तो उन्होंने दो

घोषणाएं की। एक घोषणा यह थी कि हम वहां पर किसानों के लिए 10 रुपया पर हार्स पावर कंसेशन देंगे। एक सप्ताए बाद ही हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वे गए और उन्होंने कहा कि हम 10 रुपए प्रति हार्स पावर वीवर्स को कंसेशन देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई बजटरी प्रोविजन रखा गया है? यदि नहीं रखा गया है कि उनको इसका क्या अधिकार है? संविधान के मुताबिक कोई अधिकार नहीं है कि ऐसी घोषणाएं करें। इस तरह की पापुलिस्ट घोषणाएं चुनाव को ध्यान में रखते हुए,—वहां जाते हैं और घोषणा करके आते हैं, यह उचित नहीं है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा। संक्षेप में अपनी बात कहें। समय समाप्त हो गया है।

प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा: (उत्तर प्रदेश) माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के बजट के संबंध केवल तीन बिन्दुओं की तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे मालूम है, समय कम है, इसलिए मैं कम से कम समय में अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आज जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती यदि पिछले लोक सभा के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा का भी चुनाव सम्पन्न करा लिया जाता। लोक सभा चुनाव के साथ पश्चिमी बंगाल विधान सभा का चुनाव हो गया, तमिलनाडु विधान सभा का चुनाव उसी समय सम्पन्न किया गया, केरल विधान सभा का चुनाव सम्पन्न हुआ परन्तु उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव सम्पन्न नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए उस समय चुनाव नहीं कराया गया क्योंकि उस समय की सरकार जो केन्द्र में बैठी हुई थी, उस समय की जो पार्टी केन्द्र में सत्ता में थी, वह भयभीत थी कि यदि लोक सभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव भी सम्पन्न करा लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ जाएगी। इस भय के कारण उत्तर प्रदेश की जनता को जान-बूझ कर के एक लोकप्रिय सरकार से वंचित रखा गया। इसलिए दो-दो बार इस पार्लियामेंट में लेखानुदान लाना पड़ा, अब यह बजट संसद में लाना पड़ा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती अगर समय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव होता।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के एक मुख्य मंत्री थे कुछ दिन पहले जिन्हें घोषणा मुख्य मंत्री कहा जाता था। उनका नाम घोषणा मुख्य मंत्री पड़ गया था और उत्तर प्रदेश के लोगों की यह दुखद स्थिति है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को भी घोषणा प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। जिस प्रकार से पहले के मुख्य मंत्री ने घोषणाएं की लेकिन एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया, उसी तरह से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी जब कभी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो नयी घोषणा कर देते हैं लेकिन उन घोषणाओं को लागू करने के लिए कोई बजटरी सपोर्ट नहीं, कोई बजट में प्रावधान नहीं है। जैसे गन्ना किसानों का 900 करोड़ रुपये का भुगतान होना है। ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अब आप समाप्त करें।

प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा: मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। मैं तो कभी इस सदन में बोलता नहीं, आज पहली बार बोल रहा हूं। मेरे एक साथी हैं, उनका समय कृपया मुझे दे दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपकी पार्टी का 11 मिनट का समय था।

प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा: गन्ना किसानों का मिल मालिकों पर 900 करोड़ रुपया बकाया है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम बहुत शीघ्र आधा पैसा अभी 15 दिन के अन्दर गन्ना किसानों को दिला देंगे और बाकी आधा पैसा कुछ दिन के बाद भुगतान हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान अपनी पर्चियां लिये हुए गन्ना मिलों के अधिकारियों के दरवाजे पर भटक रहा है, घूम रहा है। उन्हें एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया। वह भटक रहे हैं, उनका समय जाया जा रहा है, अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी रखा कि शुगर इंडस्ट्री को लाइसेंस मुक्त कर देंगे। यह पॉलिसी तो आपने रखी अपने मिनिमम प्रोग्राम में लेकिन ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। शीरा को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा, इसके लिए भी घोषणा नहीं हुई। किसानों के गन्ने की पेराई नहीं हुई जिससे हजारों एकड़ गन्ना मजबूर हो कर जलाना पड़ा। मैं समझता हूं यह भी एक ढपोरशंखी घोषणा साबित हुई। अभी-अभी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में घोषणा की कि हजार करोड़ लागत तक जो बिजली परियोजना होगी, उसके लिए राज्य सरकारों को केन्द्र की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि

कोई बिजली परियोजना प्रदेश में लगती है तो उसके लिए अनुदान की आवश्यकता होती है। जब तक इसके लिए कोई बजटरी प्रावधान नहीं होगा, केन्द्र से कोई सहायता नहीं मिलेगी, मैं समझता हूं कि किसी भी बिजली परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। उपसभाध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश दिन-प्रति-दिन पिछड़ता चला जा रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर है। यह इस बात से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति औसत इनकम 625 रुपये रह गई है जबकि आज हमारे इस देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय इनकम 2300 रुपये है। जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है और जो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है, उसमें एक बड़ा लम्बा गैप है। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश इस देश का दूसरा सर्वाधिक सम्पन्न प्रदेश था। आज यह बिहार के बाद में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश की तरफ पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, विशेष कर कांग्रेस की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। जो सरकारें रही वे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रहीं। कांग्रेस के जमाने में रायबरेली और अमेठी केवल दो क्षेत्रों में ही सारा पैसा दे दिया गया। सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर केवल दो प्रदेशों में बनाया गया जिससे कि भारी क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया। पिछली जो दो सरकारें थीं माननीय मुलायम सिंह जी की, उनके जमाने में भी केवल दो जिलों में विकास कार्य के नाम पर पैसा खर्च किया गया। एक तो बाराबंकी में जहां से आज हमारे वर्तमान संचार मंत्री हैं, वह क्षेत्र जहां से पहले वे विधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। जिस समय मंत्री थे उस समय उनके क्षेत्र के लिए पैसा खर्च किया गया था फिर इटावा में जसवंत नगर और जसवंत नगर में केवल एक ग्राम सेफई है जहां मैं समझता हूं कि अरबों रुपये खर्च कर दिए गए—एक छोटे से गांव में और पूरे प्रदेश को पिछड़ा रखा गया। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं कि फरूर्खाबाद में आज दस वर्ष हो गए है पांच पुलों को मंजूर हुए—एक पाण्डव नदी का पुल है औसेर के पास, एक झिन्गा नाले का पुल है ठठिया के पास, एक नेरा घाट पुर ईशन नदी का पुल है एक ईशन नदी पर दूसरा पुल है और एक काली नदी पर पुल है। ये पांच पुल हैं जिनको दस वर्ष हो गए स्वीकृत हुए जिला योजना में लेकिन आज तक एक पैसा इन पर खर्च नहीं हुआ। दस वर्ष में एक पुल नहीं बना है। इस क्षेत्रीय असंतुलन का परिणाम है कि आज उत्तरांचल में पृथक राज्य की मांग हो रही है। प्रधान मंत्री जी ने वहां राज्य बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन यह कैसे सम्पादित होगा इसके लिए कोई विधेयक नहीं लाया गया संसद में। आज बुंदेलखंड में भी पृथकतावादी आवाजें और आग की लपटें जैसी उठ रही हैं। पूर्वांचल की हालत तो बुहत खराब है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ अथवा सूखे से वहां के किसान जर्जर हो गए हैं। न बाढ़ का प्रबंध किया गया है न सूखे का प्रबंध किया गया है। बिजली की दरें कम करने की घोषणा जरूर हो गयी है लेकिन बिजली परियोजनाओं के लिए कोई स्वीकृति नहीं मिली है। आज इस केन्द्रीय सरकार के पास प्रदेश की सैकड़ों योजनाएं लम्बित हैं जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। इसीलिए प्रदेश में पिछड़ापन है। मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए, इसकी भारी जनसंख्या को देखते हुए दसवें वित्त आयोग ने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश को एडहाक रिलीफ ग्रांट के रूप में 36 हजार करोड़ रुपए देने के लिए केन्द्र सरकार से संस्तुति की थी। उस 36 हजार कोरड़ के अगेंनस्ट आज तक केन्द्र से एक भी पैसा इस उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नहीं दिया गया है। सड़कों की हालत मैं आपको बताना चाहता हूं। जनपद फरूर्खाबाद जहां से मैं आता हूं वहां की जिला योजना में 340 लाख रुपए सड़कों के लिए निर्धारित किए गए जिसमें अम्बेडकर ग्रामों को मिलाने के लिए 337 लाख रुपए और बाकी सारे जिले के लिए केवल 3 लाख रुपए। इन तीन लाख रुपयों से तो महोदया आप स्वयं समझती हैं कि एक किलोमीटर सड़क का भी निर्माण नहीं हो सकता है। जहां तक उत्तर प्रदेश की ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था है उसके बारे में मैं एक मिनट आपका लेकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं कानून व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं कि उदाहरण के रूप में अभी कल की बात है, कल इटावा में समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करने गए। उनके ऊपर गोली चलायी गयी। एक दरोगा की हत्या उसी कचहरी के अंदर हो गयी। एक कांस्टेबुल घायल हो गया।

एक माननीय सदस्यः क्या मेडन स्पीच है?

प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्माः मैं एक मिनट लेना चाहता हूं—और उनमें आपस में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। स॰पा॰ के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने यह गोली चलवायी है उम्मीदवार को जान से मार डालने की नीयत से जब कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि शासन से सुरक्षा व्यवस्था लेने के लिए जानबूझकर स॰पा॰ के लोगों ने यह धावा किया है। अभी तीन चार

दिन पहले जनपद फरूर्खाबाद में भारतीय जनता पार्टी के एक जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह की निर्मम हत्या कर दी गयी। उनके भतीजे की टांग तोड़ दी गयी। अभी तक एक भी हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ। एक सप्ताह पहले मैनपुरी में भोगांव क्षेत्र के पूर्व विधायक के भतीजे और पांच लोगों की दिनदहाड़े हत्या हो गयी और हत्या में इस्तेमाल की गयी जो कार और हत्यारे हैं आज तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पायी है। इसी तरह से जनपद एटा में 28 अगस्त को रक्षा बंधन वाले दिन कोतवाली एटा के अंतर्गत ग्राम समदपुरा के निवासी जो आगरा में एक सिपाही है जिसका नाम प्रेम सिंह है उसकी हत्या कर दी गई। उसके छोटे भाई की टांग तोड़ दी गई। उसकी मां को भी गोली मारी जिससे उसका हाथ टूट गया। उसका छोटा भाई जिसकी टांग तोड़ दी गई वह पी०ए०सी० में सब इंसपैक्टर मिनिस्ट्रियल है। सब से बड़ी बात यह है कि पुलिस ने उन हत्यारों के घर पर गार्ड बैठा दिए जिससे कि उनकी सुरक्षा हो। हत्यारों को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। जिनकी हत्या हुई उनकी सुरक्षा की कोशिश नहीं की गई बल्कि जिन्होंने हत्या की है उनके घरों पर पुलिस की फोर्स उनकी सुरक्षा के लिए बैठा दी गई।

मैंने आपके सामने इटावा, फरूर्खाबाद, मैनपुरी और एटा इन चार जिलों का उल्लेख किया है। ये चार जिले ऐसे हैं जिनमें आज के वर्तमान जो रक्षा मंत्री हैं उनका यह प्रभाव क्षेत्र कहलाता है और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आने वाले दिनों में वहां के लोग निर्भीकता से अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएं। पहले से ही इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जहां लोग आज तक निर्भीकतापूर्वक अपने वोट नहीं डाल पाए हैं। जहां मतपेटियां लूटी जाती हैं, जहां मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया जाता है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह केवल इन चार जिलों का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का ही खाका है। हमारे जो और अन्य साथियों ने कहा मैं अपनी भावनाओं को उनके साथ सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की ला एंड आर्डर व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है मैं अपने फाइनांस मिनिस्टर से कहना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो शासन है वह प्रकारान्तर से केन्द्र का शासन है। राष्ट्रपति शासन में कंट्रोल आपका है। आपको देखना चाहिए कि वहां के लोगों में विश्वास पैदा हो, कानून के प्रति आस्था पैदा हो। इसलिए मैं अपील करता हूं कि उधर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कृपया माननीय प्रधान मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, इस समय नोटिस लेने की आवश्यकता है।

इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I am grateful to hon. Members for this very brief, but valuable debate on the financial appropriations for Uttar Pradesh.

As we are debating the subject, the elections in Uttar Pradesh are underway and I hope that at the end of the exercise, there will be an elected Government and an elected Legislation in Uttar Pradesh and it will mark a new beginning for that State.

Madam, a number of points were made. I do not think it is necessary for me to deal with each of these points. I would just take a minute or two to highlight the main features of the Budget. The expenditure on Rural Development Programme is estimatd at Rs. 1,502 crores from different sources. In 1996-97, 5,000 new Ambedkar villages have been selected for providing minimum needs and facilities. Under the rural housing schemes, a provision of Rs. 71.23 crores has been made for construction of about 2,40,000 houses. The major allocations are: A million wells-scheme: Rs. 18.50 crores; rural sanitation programmes: Rs. 44.90 crores; pension for destitute persons, widows and handicapped: Rs. 47.68 crores; Kisan pension, old-age pension schemes: Rs. 97.47 crores; scholarships to students belonging to Scheduled Castes, Tribes and other backward classes and minorities: Rs. 227 crores; for rural roads and bridges: Rs. 214.82 crores; for constructionof primary schools and for boundary walls, hand-pumps and toilets of such schools: Rs 52.96 crores: additional irrigation potential to provide for minor irrigation: Rs. 111.60 crores; for water supply programmes: Rs. 101.12 crores.

It is obvious that it is not money which stands in the way of developing Uttar Pradesh. It is, I believe, and I say this with great affection for that State, that democracy must deepen, broadan and mature in that State.

5.00 P.M. And must regain the glorious tradition of the first couple of decades of that State in order that the largest, the most populous State in the Indian union gets the benefit of development and poverty is abolished.

There was some reference to Uttarakhand. The provision for Uttarakhand is Rs. 489 crores of which special hill assistance is Rs. 225 crores.

Regarding sugarcane arrears when the Prime Minister made an announcement that Rs. 900 crores was in arrears as on 31.7.1996, Rs. 450 crores, approximately 50 per cent has been paid off.

There was some reference by one of the hon. Members to the poor State of education in that State. Rs. 4,039 crores is allocated for education which is 14.90 per cent of the total budget. Yet schools are closed. Examinations are not held. There are Vice-Chancellors without Universities and unversities without Vice-Chancellors. I think we can blame no one except ourselves. I hope the people of Uttar Pradesh would realise that it is not the money which is standing in the way. It is not the lack of money which was a cause for their problems.

Madam, I do not wish to take more time in giving more information about the budget. All I wish to point out is: This is a temporary phase and a temporary arrangement and soon there would be an elected Legislature and a responsible Government. We wish the people of Uttar Pradesh all the best and we will perform our duty. I would appeal to all to join me in performing our duty by passing this Appropriation Bill so that we can move on to the next stage of governance in Uttar Pradesh. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): The question is:

> That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of a part of the financial year 1996-97, as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I move:

> "That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): There is a statement by Mr. Arunachalam.

STATEMENT BY MINISTER

Agricultural Workers (Employment, Conditions of Service & Welfare Measures) Bill, 1996

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): Madam, on 31.7. 1996, while answering the points raised during a Calling Attention Motion moved by Shri Gurudas Das Gupta, I had assured this august House that the Government are committed to alleviation of the plight of agricultural workers, are determined to come forward with a Central legislation for their protection and welfare and that this formed a specific item in the Common Minimum Programme of the Government. I had stated that our endeavour would be to